

बीकानेर संभाग में सिंचाई का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं : बुडानियां

सिंचाई और पेयजल के मुद्दे पर विधानसभा में हुई चर्चा

जयपुर। विधानसभा के तृतीय एवं बजट सत्र में बुधवार को सिंचाई एवं पीने के पानी पर चर्चा हुई जिसमें विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया और अपने क्षेत्रों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की।

सदन में अनुदान की मांग संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंद्रिया गांधी नहर परियोजना पर चर्चा शुरू हुई और इसकी शुरुआत विधायक नरेन्द्र बुडानियां ने की।

बुडानियां ने प्रदेश में पानी को महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि प्रदेश के बीकानेर संभाग में किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों के लिए फरवरी में ही पानी बंद कर दिया गया है। इससे किसान

■ प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय पानी के लिए प्रयास नहीं किए गए जबकि राज्य में भजनलाल सरकार के आते ही हरियाणा से पानी लाने पर काम किया गया : गुरवीर सिंह

आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए लेकिन किसानों के आंखों में आंसू हैं।

उन्होंने कहा कि पानी माफिया हावी होने एवं उनके अधिकारियों से मिलीभगत के कारण गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और एक हजार रुपए प्रति टैकर के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में गरीब तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि रसूखदारों के द्वारा अवैध कनेक्शन लगा लिए हैं और गरीब तक पानी पहुंचने की नहीं दिया

जा रहा है।

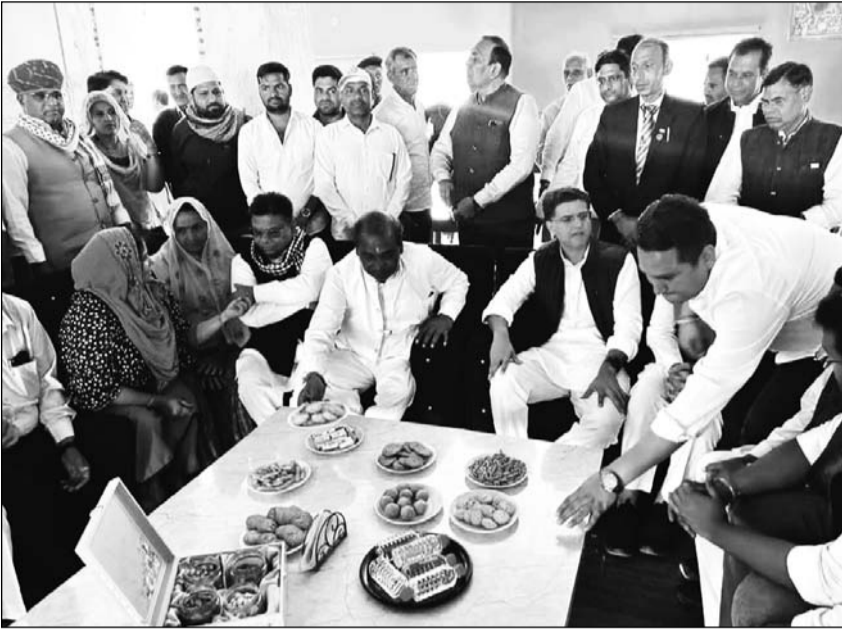
बुडानियां ने सरकार से मांग की कि अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीने का पानी गंदा आने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मॉनटरिंग कमेटी विधानसभा स्तर पर बनाई जानी चाहिए। इसी तरह जिले में कमेटी बनाई जानी चाहिए और उसमें विधायक को शामिल किया जाना चाहिए।

इसी तरह विधायक श्रवण कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश में पानी को लेकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों को लोगों को पानी उपलब्ध कराने के बारे में सोचना चाहिए और पानी की समस्या का निदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झुंझुनू, चुरु एवं सीकर जिले जहां देश की सेवा करने में सैनिकों के रूप में सबसे आगे खड़े हैं लेकिन पानी के मामले में ये जिले पीछे वाली लाइन में खड़े हैं। उन्होंने पानी की 12 हजार करोड़ की योजना को ठंडे बस्ते में पड़ी है उसका वर्क ऑर्डर कराये जाने की राज्य सरकार से मांग की।

चर्चा में भाग लेते हुए विधायक गुरवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय पर पानी के लिए प्रयास नहीं किए गये जबकि राज्य में

भजनलाल सरकार के आते ही हरियाणा से पानी लाने पर काम किया गया। उन्होंने वर्षों जल संचयन की जरूरत बताते हुए कहा कि इस पर और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जनआंदोलन के रूप में लेना चाहिए। विधायक अमित चाचाण ने अपने नोहर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने का मामला उठाते हुए कहा कि हरियाणा से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी दिलाया जाना चाहिए ताकि किसानों को पूरा पानी मिल सके। उन्होंने उनके क्षेत्र में किसानों की डिगियों के निर्माण के काम को भी पूरा कराये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज भी कई घरों तक पानी नहीं पहुंचा है ऐसे में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए।

भाजपा के मंत्रियों में आपसी समन्वय का अभाव है : पायलट



टोंक में राजमिहवे होटल पर कांग्रेसजनों ने बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वर्तमान टोंक विधायक सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया।

टोंका पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वर्तमान टोंक विधायक सचिन पायलट अल्प प्रवास पर टोंक आये तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद यहां उन्होंने प्रेस से मिलकर बताया कि टोंक में जो प्रोजेक्ट शुरू किये गये थे उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। विशेष रूप से नगर परिषद से जुड़े वे सभी कार्य जो कांग्रेसकाल में शुरू थे वे सभी पूरे किये जायेंगे। जिले में मीठे पानी को लेकर कन्ट्रोल्स प्लान बनाये गये हैं, जो एक-दो महिने में ही पूरे हो जायेंगे। घनातलाई प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि उसके गन्दे पानी की निकासी कर, उसका सौन्दर्यकरण का कार्य भी होना है, जियके लिए मैं दो करोड़ की राशि पूर्व में दे दी चुका हूं।

■ 'जूली व डोटसरा के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है लेकिन किरोडीलाल मीणा आज मंत्री भी है या नहीं यह संदेह बना हुआ है'

नगर परिषद टोंक द्वारा सीवरेज, ड्रेनेज व शहर की साफ-सफाई का कार्य किया जाना है, जिसके लिए नगर परिषद को और बजट राशि दिलावारी जाने के हमारे प्रयास रहे। वहीं विपक्ष की भूमिका के सम्बन्ध में पायलट ने कहा कि जूली व डोटसरा के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है, किरोडीलाल मीणा आज मंत्री भी है या नहीं यह संदेह बना हुआ है। भाजपा की राज्य सरकार में

अधिकारी ही हावी है, सरकार तो सिर्फ घोषणाये व भाषणबाजी ही कर रही है। भाजपा के मंत्रियों में आपसी समन्वय का पूरा अभाव है। टोंक सहित राज्यभर में बलात्कार की घटनायें बढ़ रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा को लेकर वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। भाजपा के इस कार्यकाल में अब तक यह स्थान नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं। क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन को लेकर माफियाओं को नियंत्रण करने में सरकार असफल रही है, यह सरकार केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रही है। सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, कांग्रेस ने दलित आवाज बहुत मजबूती से उठाई है। अपनी साईकिल यात्रा के सम्बन्ध में पायलट ने कहा कि यह यात्रा युवा वर्ग को नशे से दूर रखने का संदेश देने हेतु यह यात्रा की गई है, यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, टोंक में भी जिला प्रशासन के सहयोग से नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाये जाने की जरूरत है।

इससे पूर्व राजमिहवे होटल पर कांग्रेसजनों ने पायलट का भव्य स्वागत किया, इसके बाद पायलट मुकुल परिवार के यहां शोक सतर्क परिवार को ढाढस बांधने पहुंचे तथा वही पूर्व भाजपा की पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन के यहां सम्पन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम में वर-वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे, वही एडवोकेट कदीर के यहां पहुंचकर परिवार को साल्ना प्रकट की। पायलट ने टोंक शहर सहित ग्राम लक्ष्मीपुरा (छानबाससूर्या), ग्राम सैतौवास (खरेडा) तथा ग्राम संवारिया (मालपुरा) में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की।

प्रेस वार्ता के दौरान पायलट ने पत्रकारों के साथ भोजन किया, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा, दिनेश चौधरी, कमल बैरवा, शिवपाल खंडवा, राजेंद्र गोयल, हेमराज गाथा, अन्दूल खालिक, धमंशर सालोदिया, मयंक गोयल, शैलेश गुर्जर, पूर्व सरकारी पीपी राजेश गुर्जर, सतवीर गुर्जर आदि उपस्थित रहे।

भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़ी शिक्षा का हो प्रभावी प्रसार : राज्यपाल



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार ने हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान 'रीपा' में इंद्रिया गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान किया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें ही नहीं विद्यार्थी जीवन व्यवहार और नित नए हो रहे परिवर्तनों से जुड़ी सामग्री को भी अध्ययन करे। इसी से उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और वे जीवन में सफल हो सकेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाए जाने के लिए भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़ी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का भी आह्वान किया।

बागडे ने बुधवार को हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान 'रीपा' में इंद्रिया गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ज्ञान-विज्ञान में आरंभ से ही समृद्ध रहा है। यहां नालंदा जैसा महान विश्वविद्यालय था। यहां सुदूर देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उन्होंने बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जलाने की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान को नष्ट करने के निरंतर प्रयास हुए परन्तु वे सफल नहीं हुए। उन्होंने राजस्थान को शूरवीरों की भूमि बताते हुए कहा कि ब्याज रावल ने सौ सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों को यहां आने नहीं दिया।

राज्यपाल ने आरंभ में इंद्रिया गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा रोजगार के साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करने वाले, श्रमिकों आदि को भी डिग्री प्रदान कर सफल होने का रिकॉर्ड संचारित किए जाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने इससे पहले इन्फो के रिजल सेंटर की गतिविधियों की प्रदर्शनी लोकार्पण किया। इससे पहले क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ममता भाटिया ने इन्फो के पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। राममूर्ति मीना ने सभी का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल ने इससे पहले इन्फो के रिजल सेंटर की गतिविधियों की प्रदर्शनी लोकार्पण किया। इससे पहले क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ममता भाटिया ने इन्फो के पाठ्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। राममूर्ति मीना ने सभी का आभार व्यक्त किया।

ट्रेनिंग पर हुआ खर्च जमा कराने के लिए आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के दूसरी नौकरी के लिए पद छोड़ने के मामले में आदेश दिये हैं कि वह परिवोक्षा काल में ट्रेनिंग पर हुए खर्च को पुलिस विभाग में जमा कराए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कांस्टेबल को इस खर्च में दिए वेतन की वसूली नहीं की जाएगी। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश को और से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण खर्च हुई राशि निर्धारित कर चार सप्ताह में इसकी जानकारी मुहैया कराए। वहीं याचिकाकर्ता एक माह में इस राशि को जमा कराए। अदालत ने कहा कि राशि जमा होने पर विभाग उसे एसओसी जारी करे। अदालत ने याचिकाकर्ता को संगणक पद पर कार्य ग्रहण करने की सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि यदि तय अवधि में याचिकाकर्ता राशि जमा नहीं करता है तो पुलिस विभाग उसे वापस बुलाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अदालत ने अपने आदेश में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण खर्च हुई राशि निर्धारित कर चार सप्ताह में इसकी जानकारी मुहैया कराए। वहीं याचिकाकर्ता एक माह में इस राशि को जमा कराए। अदालत ने कहा कि राशि जमा होने पर विभाग उसे एसओसी जारी करे। अदालत ने याचिकाकर्ता को संगणक पद पर कार्य ग्रहण करने की सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि यदि तय अवधि में याचिकाकर्ता राशि जमा नहीं करता है तो पुलिस विभाग उसे वापस बुलाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

जीएसएस निर्माण के कार्यादेश जल्द : नागर

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त करते हुए कहा कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विर धोलिया में 400 केवी जीएसएस के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है और निविदा कार्य पूरा होते ही इस जीएसएस के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किया जायेगा, जिससे गर्मियों में उदयपुर ग्रामीण के जनजातीय क्षेत्रों में निर्बाध

विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। नागर प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि घरती आबा जनजातीय ग्राम उकरवं अभियान के तहत उदयपुर ग्रामीण के 31 गांवों में एक हजार से अधिक विद्युत कनेक्शन देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। स्वीकृति उपरांत ऑन ग्राइड कनेक्शन दिए जाएंगे।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी को आईफा अवाडर्स समारोह के आयोजकों ने बुधवार को सचिवालय में मुलाकात कर, समारोह में शामिल के लिए निमंत्रण दिया। आईफा अवाडर्स आयोजन समिति के सदस्य स्वभाव जोसेफ, कविता वकील ने 8 एवं 9 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले आईफा समारोह में उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति के लिए अनुरोध किया।

होम गार्ड जवानों के नियोजन में पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम विकसित : खराड़ी

जयपुर (वि.स.)। गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि होम गार्ड्स के नियोजन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिस्टम विकसित किया गया है। खराड़ी प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

■ गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रश्नकाल में विधायक लक्ष्मण राम के प्रश्न पर जवाब दिया

अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ की सुविधा देय नहीं है।

व्यापारी के लापता होने का मामला सदन में उठा

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को नीमकाथाना क्षेत्र के डाबला के एक व्यापारी के लापता हो जाने का मामला उठा। शून्यकाल में विधायक सुरेश मोदी ने स्थान प्रस्ताव के तहत यह मामला उठाते हुए बताया कि डाबला में अपना व्यापार कर रहे सुनील जांगिड़ एक मार्च को जयपुर आये थे और उनके पास देनदारियां चुकाने एवं खरीददारी के लिए धनराशि भी थी। व्यापारी ने शाम को घर पर फोन करके बताया भी था कि उसका थोड़ा काम शेष रह गया है और वह रात में या सुबह घर लौट आयेगा।

उन्होंने कहा कि होमगार्डों को नियमित रोजगार देने के संबंध में कोई निर्धारित मापदंड तय नहीं है।

इससे पहले विधायक लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 में संशोधन कर होम गार्ड्स सेवा नियम बनाए जाने एवं होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको कर्मचारी भविष्य निधि

युवा संसद में 9 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन

जयपुर। राजकीय महाविद्यालय, जयपुर द्वारा विकसित भारत युवा संसद का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, युवाओं की आवाज को बढ़ाना, सार्वजनिक मुद्दों में युवाओं के निर्णय लेने के कौशल और विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देना है।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. निन्हा शर्मा ने बताया कि इसमें युवाओं को 09 मार्च तक माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर विकसित भारत से आप क्या समझते हैं। विषय पर 01 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा जिसमें चयनित 150 प्रतिभागियों की ऑफलाइन प्रतियोगिता 11-12 मार्च, 2025 को महाविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें चयनित 10 प्रतिभागियों को राज्यस्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में विधान सभा जयपुर में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके पश्चात इनमें से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से तीन प्रतिभागी चयनित हो कर राष्ट्रीय स्तर पर संसद भवन नई दिल्ली में केन्द्र स्तर के कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दौसा जिले के 18 से 25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं।

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव जन जागरूकता अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने प्रेसवार्ता कर बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि, अलग-अलग और बार-बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसे प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के पांच जिलों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सफल प्रयोग के पश्चात इस सिस्टम को संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश के विभिन्न राजकीय उपक्रमों में नियोजित होमगार्डों की ड्यूटी की समयावधि का वास्तविक आकलन हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा दो के अनुसार होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है। जिन्हें मांग के आधार पर, आवश्यकता होने पर विभिन्न राजकीय उपक्रमों में नियोजित किया जाता है।

जयपुर। सदन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को ब्लैकमेल करने वाले एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर आरोपी एक महिला को परेशान कर रहा था। इसी दौरान निर्भया की टीम मौके पर पहुंची। जहां निर्भया टीम को महिला ने आरोपी के बारे में बताया कि वह उसे नहीं जानती कई समय से वह उसे परेशान कर रहा है। जिस पर निर्भया ने आरोपी को डिटेन किया और सदर थाने लेकर पुलिस को सौंपा। जहां आरोपी ने खुद को पत्रकार बताया और उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो आरोपी के पास फर्जी दस्तावेज मिले। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जयपुर। सदन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को ब्लैकमेल करने वाले एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर आरोपी एक महिला को परेशान कर रहा था। इसी दौरान निर्भया की टीम मौके पर पहुंची। जहां निर्भया टीम को महिला ने आरोपी के बारे में बताया कि वह उसे नहीं जानती कई समय से वह उसे परेशान कर रहा है। जिस पर निर्भया ने आरोपी को डिटेन किया और सदर थाने लेकर पुलिस को सौंपा। जहां आरोपी ने खुद को पत्रकार बताया और उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो आरोपी के पास फर्जी दस्तावेज मिले। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि जयपुर कमिश्नर और निर्भया की नोडल प्रभारी के दिशा निर्देशन में जयपुर पुलिस की निर्भया को सिविल टीम

एक राष्ट्र, एक चुनाव देश के लिए नई व्यवस्था नहीं, पहले भी देश में हो चुके एक चुनाव : सुनील भार्गव

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव जन जागरूकता अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने प्रेसवार्ता कर बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि, अलग-अलग और बार-बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है।

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव जन जागरूकता अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने प्रेसवार्ता कर बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि, अलग-अलग और बार-बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है।

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव जन जागरूकता अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने प्रेसवार्ता कर बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि, अलग-अलग और बार-बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है।

भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया

के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है और नीति संबंधी निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है जिसके लिए गहरा विचार-विमर्श और आम सहमति की आवश्यकता है।

एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नई नहीं है। संविधान की अंतर्भाव किए जाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और

राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही। हालांकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया। जबकि, आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं। जबकि छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।

राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही। हालांकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया। जबकि, आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अक्टूबर 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं। जबकि छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।